दोहरा खतरा। हालांकि, उस मामले में सेवा नियमों नेदूसरी जांच को छोड़ दिया। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

(?) परिणामस्वरूप, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और याचिकाकर्ता के खिलाफ दूसरी विभागीय जांच शुरू करने के आदेशों को रद्द करता हूं। शेष आदेश लागू रहेगा। मैं जांच की कार्यवाही भी रद्द करता हूं। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस फैसले का हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह और बनवारी लाल के खिलाफ जांच कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

एन.के.एस.

एस. पी. गोयल से पहले जे.

शंभू दयाल, अपीलकर्ता।

बनाम

श्रीमती तारावंती और ओटीआरईआरएस, - उत्तरदाता।

1975 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 867।

23 सितंबर, 1983।

परिसीमा अधिनियम (1908 का IX) - अनुच्छेद 148 - बंधक संपत्ति का प्रतिदान - बंधक विलेख में शर्त जो अतिरिक्त राशि के भुगतान पर दस वर्षों के भीतर पुनर्भुगतान को सक्षम बनाती है - दस वर्षों के भीतर भुनाने का विकल्प - भुनाने का अधिकार - क्या दस वर्ष की समाप्ति के बाद प्राप्त होता है - *60* वर्ष के बाद लेकिन 70 वर्ष की समाप्ति से पहले दायर की गई जमानत के लिए मुकदमाबंधक की तारीख से वर्षों तक - ऐसा मुकदमा - चाहे सीमा के भीतर हो।

यह माना गया कि बंधक-विलेख में अतिरिक्त राशि के भुगतान पर दस वर्षों के भीतर मोचन की अनुमति देने की शर्त केवल एक अनिवार्य प्रावधान था जो बंधककर्ता के लाभ के लिए था। यह उसके लिए खुला था कि वह दस साल की अवधि के भीतर संपत्ति को भुना सकता था यदि वह अतिरिक्त राशि के भुगतान पर ऐसा चाहता था। यदि वह उस विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो दस वर्षों के लिए पुनर्भुगतान की सीमा की शर्त पूरी तरह से लागू थी और भुनाने का अधिकार दस साल की समाप्ति के बाद ही बन्धककर्ता को प्राप्त होना था। इसलिए, बंधक संपत्ति के मोचन के लिए मुकदमे में सीमा समझौते में निर्धारित दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद ही शुरू होगी और यदि मुकदमा 60 वर्षों के बाद लेकिन बंधक की तारीख से 70 वर्ष की समाप्ति से पहले दायर किया जाता है, तो यह समय के भीतर होगा।

(सेवा 2)

अंबाला (गुडगांव में शिविर) के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री के एल वासन की अदालत के दिनांक 25 मार्च, 1975 के आदेश से नियमित द्वितीय अपील, जिसमें श्री पी पी छाबड़ा, उप न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, बल्लभगढ़ द्वारा दिनांक *11* जून, 1974 को वादी के वाद को खारिज कर दिया गया था और पक्षकारों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया था। क्रॉस आपत्तियों को भी खारिज कर दिया गया।

अपीलकर्ताओं की ओर से एम. एस. जैन, अधिवक्ता।

प्रतिवादी की ओर से वकील कमलजीत बख्शी के साथ वकील अरुण जैन।

निर्णय

एस. पी. गोयल, जे.

(1) अंबाला के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले और डिक्री के खिलाफ इस दूसरी अपील में, एकमात्र और महत्वपूर्ण बिंदु जिसे निर्धारित करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या मोचन के लिए मुकदमा समय द्वारा रोक दिया जाता है।

(2) उक्त प्रश्न के निर्धारण के लिए,पक्षकारों की दलीलों का विस्तार से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है और केवल उन तथ्यों पर ध्यान देना पर्याप्त होगाजो उस उद्देश्य के लिए आवश्यक हैं। विवादित संपत्ति को अपीलकर्ता के पूर्व-हित कर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के पूर्ववर्ती-हित के साथ बंधक विलेख, प्रदर्शनी पी -2, दिनांक 18 दिसंबर, 1905 के माध्यम से 900 रुपये के विचार के लिए गिरवी रखा गया था । इसके पुनर्निर्धारण के लिए यह मुकदमा22 दिसंबर, 1970 को 60 साल की समाप्ति के बाद दायर किया गया था, यानी निर्धारित सीमा की अवधि। हालांकि, वाद को मोरिंग डीड की शर्त संख्या 6 के आधार पर सीमा के भीतर होने का दावा किया गया था,जो निम्नानुसार है: –

> "SHARAT FAKUL REHAN BA HAD MIAD DAS SALL KE KARAR PAI HAI. ZAN KUL ZAR PATTA, ZAR HAHAN WA LAGGA WA SOOD KE YAKMUSHT MURATAHANAN KO DE DENGA. DUKAN MARHUNA FAKUL REHAN KAR DENGE AGAR AND-ROON MIYAD MURKARAH GUJAST KARENGA TWOO BAJAI MUBLIGH 900 KE MUBLIGH 990 ZAR REHAN WA SOOD WA LAAGAT KE JO WAJIB TALAB HOGA? DENDAR HONGE."

नीचेदी गई अदालतों ने यह विचार लिया है कि चूंकि यह बंधक के लिए खुला था कि वह तारीख के बाद किसी भी समय संपत्ति को भुना सकता है।

Shambhu Dayal बहुत। श्रीमती तारावंती और अन्य (एस. पी. गोयल, जे.

बंधक राशि के भुगतान पर 90 रुपये के साथ बंधक की तारीख से ही भुनाने का अधिकार शुरू हो जाता है। हालांकि, इस दृष्टिकोण को कानून में बनाए नहीं रखा जा सकता है। उक्त खंड केवल एक सक्षम प्रावधान था जो बन्धककर्ता के लाभ के लिए था। यदि वह 90 रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना चाहता है, तो वह दस साल की अवधि के भीतर पैसे का भुगतान कर सकता है। यदि वह उस विकल्प का उपयोग नहीं करता है, तो 10 साल के लिए मोचन की सीमा की शर्त पूरी तरह से लागू थी और भुनाने का अधिकार 10 सालकी समाप्ति के बाद ही बंधक को प्राप्त होना था। यद्यपि वर्तमान स्थिति को कवर करने वाला कोई प्रत्यक्ष प्राधिकार नहीं है, लेकिन बख्तावर बेगम बनाम भारत में प्रिवी काउंसिल की कुछ टिप्पणियां हैं।हुसैनी खानम और अन्य, (1), मेरे विचार का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उस मामले में, बन्धककर्ता ने 12 गांवों के शेष भाग में सशर्त बिक्री के माध्यम से बंधक निष्पादित किया। बन्धककर्ता द्वारा बन्धककर्ता के साथ एक समकालीन करार किया गया था कि बन्धककर्ता किसी भी समय 9 वर्ष की अवधि के भीतर उस संपत्ति को वापस लेने का दावा कर सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस खंड की व्याख्या करते हुए कहा कि ऋण 9 साल की अवधि के लिए बकाया रहा और भुनाने का अधिकार केवल उस अवधि की समाप्ति पर अर्जित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप मुकदमा सीमा के भीतर माना गया। मुकदमे को सीमा के अनुसार मानने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को एक अन्य विचार पर उलट दिया गया था, लेकिन जहां तक उक्त खंड की व्याख्या का संबंध था, प्रिवी काउंसिल के उनके लॉर्डशिप ने इस प्रकार टिप्पणी की: -

> "आम तौर पर, और एक विशेष शर्त के अभाव में, जिसके लिए बंधक बनाया गया है, उस अवधि के दौरान भुनानेके लिए बंधककर्ता को बाध्य करना , मोचन का अधिकार केवल निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पार्टियों को यह प्रावधान करने से रोकता है कि बंधक धारक निर्धारित अवधि के भीतर ऋण का निर्वहन कर सकता है और संपत्ति वापस ले सकता है। ऐसा प्रावधान आमतौर पर बंधककर्ता के लाभ के लिए होता है। वर्तमान मामले में, यदि मामला केवल अनुबंध के निर्माण पर निर्भर करता है जैसा कि कलेक्टर की कार्यवाही में दिया गया है, तोउच्च न्यायालय के निष्कर्षों के समर्थन में कहा जा सकता है।

उपरोक्त टिप्पणी से, यह स्पष्ट है कि समकालीन समझौते पर उच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्माण और इसके

(1) I.L.R. 36, Allahabad 195.

यह पाते हुए कि 9 साल की अवधि के बाद अर्जित रिडीम का अधिकार प्रिवी काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया था। वर्तमान मामले के तथ्य बेहतर स्थिति में हैं क्योंकि यहां बंधक कर्ता को 90 रुपये का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता था यदि वह 10 वर्षों के भीतर मोचन के अपने विकल्प को समाप्त करना चाहता था और यदि वह उस विकल्प का उपयोग नहीं करता है, तो वह दस साल की समाप्ति से पहले संपत्ति को भुनाने का हकदार नहीं था। इसलिए, वर्तमान मामले में सीमा समझौते में निर्धारित 10 वर्ष की प्रति वर्ष की समाप्ति के बाद ही शुरू हुई और इस प्रकार वर्ष 1970 में दायर मुकदमा समय के भीतर था।

52
2

(3) ऊपर दर्ज कारणों के लिए, इस अपील को स्वीकार किया जाता है, आक्षेपित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया जाता है और अपीलकर्ता की ओर से मोचन के लिए एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है,इस आशय से कि यदि वह 31 दिसंबर, 1983 को या उससे पहले अदालत में 900 रुपये की राशि का भुगतान करता है, तोप्रतिवादी वादी को या ऐसे व्यक्ति को प्रदान करेगा जो वादी सभी दस्तावेजों को कब्जे में रखता है या अधिकार में रखता है।बंधक संपत्ति को जब्त करना और यदि ऐसा हो तो प्रतिवादी या उसके अधीन दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा बनाए गए बंधक और सभी दायित्वों से मुक्त अपनी लागत पर वादी को संपत्ति को फिर से हस्तांतरित करना होगा और वादी को मुकदमा संपत्ति के कब्जे में भी रखेगा। आगे यह आदेश दिया जाता है कि यदि अपीलकर्ता निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो यह अपील खारिज कर दी जाएगी। अपील में शामिल जटिल प्रश्नों को देखते हुए, पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। 4

एन.के.एस . पूर्ण बेंच

पी.सी. ज्वाइन से पहले ए.सी.जे., डी.एस.तेवतिया और आई.एस.तिवाना, जे.जे.

जगतार सिंह, याचिकाएं।

बनाम

अतिरिक्त निदेशक, समेकन ऑफ होल्डिंग्स, पंजाब और अन्य, उत्तरदाता।

सिविल रिट याचिका सं. 1981 का 2343 ।

21 फरवरी, 1984।

ईस्ट पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और भ्रष्टाचार निवारण)अधिनियम (1948 का एल) - धारा 42 - पूर्वी पंजाब होल्डिंग्स (समेकन और विखंडन की रोकथाम)'R^—नियम

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

रेवाड़ी, हरियाणा